G20 भारत 2023 INDIA
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

U20 AHMEDABAD 2023
वसुधैव कुटुम्बकम्
ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE

Ministry of Housing and Urban Affairs
Government of India

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Azadi Ka Amrit Mahotsav

स्वच्छ वार्ता

महिला विशेष संस्करण

स्वच्छ भारत मिशन–शहरी 2.0

न्यूजलेटर

SWACHHOTSAV

#WomenLedSanitation

A Swachh Bharat Mission Urban Initiative

Ministry of Housing and Urban Affairs

Government of India

महिला सशक्तीकरण के प्रयासों के परिणाम स्पष्ट नजर आ रहे हैं और हम देश के सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन का अनुभव कर रहे हैं।

नरेंद्र मोदी
प्रधानमंत्री

SWACHH VAARTA
NEWSLETTER
महिला विशेष संस्करण । मार्च 2023

चर्चा में...

SWACHH TSAV

#WomenLedSanitation

A Swachh Bharat Mission Urban Initiative

एक बड़ा परिवर्तन लाने की दिशा में महिलाएं विशेष योगदान दे सकती हैं। वे नया रास्ता दिखाने वाली हैं, पूरी तस्वीर को बदल सकती हैं और उनमें नेतृत्व कुशलता भी है। वे केवल अपने घरों में ही नहीं, बल्कि पूरे समाज में अनादि काल से स्वच्छता की ध्वजवाहक रही हैं। शहरों में स्वच्छता के प्रति उनके योगदान और प्रभाव को सामने लाने के लिए 7 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत तीन सप्ताह तक चलने वाले महिलाओं के नेतृत्व वाले विशेष स्वच्छता अभियान 'स्वच्छोत्सव' का शुभारंभ किया।

स्वच्छोत्सव का उद्देश्य 'स्वच्छता की दिशा में महिलाओं के योगदान' से आगे बढ़कर 'महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता' को पहचानकर उसका उत्सव मनाना है। इसके अंतर्गत 8 से 30 मार्च तक विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं के योगदान के सम्मान में उत्सव मनाने लिए शहरों में कई कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की गई है।

अभियान में किए जा रहे प्रयास

विन्स अवॉर्ड्स 2023 – विमेन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता (WINS) अवॉर्ड्स 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता को पहचानना और उसका जश्न मनाना है।

स्वच्छता यात्रा – स्वच्छता दूत विभिन्न शहरों में यात्रा कर क्षमता निर्माण और एक-दूसरे से सीखने की प्रक्रिया का प्रसार करेंगे और महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ विशेष प्रयासों को साझा करेंगे।

जीएफसी इंफ्लुएंसर्स नेटवर्क – एसबीएम-यू 2.0 को सफल बनाने में साझेदारों के रूप में स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों को मुख्यधारा में लाने में मदद करेंगे। जीएफसी इंफ्लुएंसर्स मिशन के लक्ष्य के बारे में जागरूकता पैदा करेंगे।

स्वच्छ मशाल मार्च – स्वच्छ मशाल मार्च का उद्देश्य 'कचरा मुक्त शहरों' के लक्ष्य की ओर नागरिकों को वार्ड-स्तर पर एकजुट करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

SWACHHATA YATRA

तेलंगाना की 30 विमेन वेस्ट एंटरप्रेन्योर्स ने स्वच्छता दूत के रूप में ओडिशा, केरल और कर्नाटक की यात्रा की। 35 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से आने वाली महिलाएं 3 सप्ताह के स्वच्छोत्सव के दौरान कचरा मुक्त शहरों के लिए रोमांचक 'विजिट-एक्सचेंज लर्न' यानी यात्रा के दौरान एक-दूसरे से अनुभव साझा कर सीखने की पहल में 14 मेजबान राज्यों की यात्रा करने के लिए तैयार हैं।

असम के स्वच्छता दूतों ने स्वच्छता यात्रा के हिस्से के रूप में कुछ नया सीखने और एक-दूसरे से सर्वोत्तम प्रयास साझा करने के लिए अंबिकापुर, छत्तीसगढ़ का दौरा किया।

मध्य प्रदेश से स्वच्छता दूतों को रेलवे स्टेशन से स्वच्छता यात्रा शुरू करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मंजिल है गुजरात!

तेलंगाना में शमशाबाद के जीएफसी इन्फ्लुएंसर नेटवर्क से उत्सव की झलकियां। इस आयोजन ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वच्छता और राजनैतिक समेत अन्य सभी क्षेत्रों में महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया।

विन्स (WINS) अवॉर्ड्स 2023 (विमेन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता)

स्वच्छ भारत मिशन-शहरी ने स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में महिलाओं के लिए आजीविका और कौशल विकास के अवसर उत्पन्न करते हुए सुरक्षित स्वच्छता और महिलाओं की गरिमा को ध्यान में रखते हुए अपनी पहुंच को सक्षम बनाया है। अब हम 'स्वच्छता की दिशा में महिलाओं के योगदान' से 'महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता' की ओर एक परिवर्तनकारी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में उनके प्रभाव को सामने लाने करने के लिए माननीय केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 7 मार्च 2023 को 'विमेन आइकॉन्स लीडिंग स्वच्छता' (WINS) अवॉर्ड्स 2023 की घोषणा की। विन्स अवॉर्ड्स 2023 का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले संगठनों और व्यक्तिगत रूप से महिलाओं द्वारा शहरी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन में प्रेरक और अनुकरणीय पहलों का जश्न मनाना और उनका प्रसार करना है।

WINS Awards 2023
Women IcoNs leading Swachhata

Nominate a woman champion & celebrate their exemplary work in swachhata

Start date for nominations:
8th March 2023

Deadline for nomination:
14th April 2023

More Info on:
https://sbmurban.org/wins-awards-2023

GFC INFLUENCERS' NETWORK
GARBAGE FREE CITIES

जीएफसी (कचरा मुक्त शहर) इंफ्लुएंसर्स नेटवर्क

जीएफसी इन्फ्लुएंसर अपनी ही शैली में स्वच्छता की पहल कर रहे हैं और दूसरों को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए प्रभावित कर रहे हैं, इस तरह से वे स्वच्छता के अभियान को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अभियान का उद्देश्य ऐसी सक्रिय महिलाओं की शक्ति को दिशा देना है जो बड़ा परिवर्तन लाने में अहम भूमिका निभा सकती हैं। स्वच्छोत्सव के दौरान स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शहरों द्वारा पूरे भारत में 75,000 जीएफसी इन्फ्लुएंसर यानी कचरा मुक्त शहर बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स का नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। स्वच्छता की दिशा में नेतृत्व क्षमता दिखाने और मुख्यधारा में लाकर अनुकूल वातावरण बनाने के लिए इन महिला स्वच्छता योद्धाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा।

(Swachhata Warriors) स्वच्छता के योद्धा

पुणे की लेडी सिंघम ने स्वच्छता की राह चुनकर सुनिश्चित की सुरक्षा: हेल्थ इंस्पेक्टर कविता

जैसे ही साल 2020 की शुरुआत हुई, दुनिया के सामने कोविड-19 नामक महामारी एक चुनौती के रूप में खड़ी हो गई। इस महामारी ने दुनिया भर में अरबों लोगों के जीवन को झकझोर कर रख दिया और जीवन के प्रति लोगों के नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी दौरान पुणे की स्वास्थ्य निरीक्षक कविता कविता सिसोलेकर ने लेडी सिंघम के रूप में स्वच्छता की राह चुनकर लोगों की जिंदगी बचाने की दिशा में कदम बढ़ाया। उन्होंने पुणे के 54,000 की आबादी वाले घोले रोड और बिबवेवाड़ी क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों की देखभाल के लिए खुद को समर्पित कर दिया। कविता ने उन लोगों के पास पहुंचकर साफ-सफाई के बारे में जागरूक किया। साथ ही एकजुटता से COVID का सामना करने के लिए व्यवहार परिवर्तन कार्यक्रम के तहत सूचना का प्रसार करने का बीड़ा उठाया। अगस्त से अक्टूबर 2021 तक, कविता सिसोलेकर ने महाराष्ट्र के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले कमजोर समूहों को वॉश (जल, सफाई और स्वच्छता) आपूर्ति और सेवा वितरण के माध्यम से आईपीसी (संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण) के बारे में जागरूक करने के लिए सामुदायिक पहुंच सुनिश्चित की।

जयाबाई: सामाजिक न्याय के मानदंड स्थापित करने वाली एक महिला नेता

जयाबाई गोसांगी के आदिवासी समुदाय से हैं। परंपरागत रूप से आदिवासी समुदायों का नेतृत्व हमेशा एक पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता रहा है। हालांकि, जयाबाई ने लंबे समय से चली आ रही इस रूढ़िवादी सोच को तोड़ दिया। वे बहुत पिछड़े तबके से निकलकर समुदाय की पहली महिला लीडर बनीं। जबकि उनके पति और बेटे अभी भी झुग्गी क्षेत्र के पास एक ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर (DWCC) का संचालन करते हैं, जो उनकी आय का प्रमुख स्रोत है। वहीं जयाबाई ने कचरा बीनने का अपना काम छोड़कर खुद को स्थायी सामुदायिक विकास के प्रति समर्पित कर दिया। उन्होंने मेन्स्ट्रुअल हाईजीन पर बोलते हुए काफी साहसी प्रयास किया। वे सामाजिक न्याय के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ीं और सभी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में शिक्षित किया। जयाबाई ने अपने समुदाय की किशोरियों और युवतियों को वॉटरऐड द्वारा आयोजित कई मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन सत्रों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। वे न केवल मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता प्रबंधन से संबंधित संदेशों को दोहराकर वॉटरऐड टीम का समर्थन कर रही हैं, बल्कि उपयोग के बाद मासिक धर्म अवशोषक के सुरक्षित निपटान के बारे में भी जागरूक कर रही हैं।

(Swachhata Warriors) स्वच्छता के योद्धा

समावेशी स्वच्छता को आकार देता महिलाओं का नेतृत्व

जयपुर में अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र से आने वाली महिला नेताओं के एक समूह ने फैसला किया कि यह आवाज उठाने का समय है, ताकि सभी के लिए सुरक्षित स्वच्छता व्यवस्था के उद्देश्य को आकार मिले। उन्होंने समुदाय के सदस्यों को संगठित करने, सूक्ष्म योजना बनाने, स्वच्छता संबंधी सुधारों को सह-निष्पादित करने और समुदाय के समर्थन में ऑपरेशन और मेंटेनेंस के साथ इसे बनाए रखने के लिए शुरू से अंत तक जोड़ने के लिए काम किया। यह कहानी मंजू राणा, संजू राणा, छुट्टन बेगम, मदीना, कैलाशी, मिर्ची, लक्ष्मी, सुनीता जैसी महिलाओं की है, जिन्होंने बाबारामदेव नगर बस्ती, जयपुर में महिलाओं समेत हाशिए पर रहने वाले अन्य वर्गों के लिए व्यापक रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कचरा बीनने वालों के लिए समावेशी स्वच्छता की दिशा में काम किया। उन्होंने खुद को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (SWM) के तहत प्रशिक्षित करने का फैसला किया। उन्होंने SWM पर केंद्रित 15 प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया और 200 सामुदायिक स्वयंसेवकों के लिए खतरा बनने वाले कचरे के गड्ढों को सुरक्षित रूप से खाली किया। जून 2021 तक, प्रत्येक लीडर ने हर एक विशेष समूह तक पहुंचने की जिम्मेदारी ली, जिसमें बुजुर्ग, अकेली महिलाएं, दिव्यांग आदि तक शामिल हैं। लीडर्स ने 400 से अधिक समुदाय के सदस्यों को सुरक्षित स्वच्छता संबंधी प्रयासों और स्रोत पर ही कचरे को अलग करने के प्रति जागरूक करने के लिए स्थानीय अभियान चलाए। जिन 100 घरों में शौचालय नहीं था, उनमें से 25 में शौचालय बनवाए गए और बाकी 75 बनाए जा रहे हैं।

अमृतसर में एक दृढ़ संकल्प की कहानी बयां करतीं देवी रानी

देवी रानी अमृतसर में बांग्ला कॉलोनी के सभी निवासियों के लिए एक बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं, जहां ज्यादातर कचरा बीनने वाले और सफाई कर्मचारी रहते हैं और उन्हें सफाई साथी के नाम से जाना जाता है। कॉलोनी की प्रधान के रूप में वे न केवल अपने समुदाय में बल्कि दूर-दूर तक कूड़ा बीनने वालों के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। आज वे यूएनडीपी इंडिया और कोका कोला इंडिया फाउंडेशन (आनंदना) परियोजना के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और आजीविका उत्पादन पर सात स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) की प्रमुख हैं, जिसमें फिनिश सोसाइटी कार्यान्वयन भागीदार है। इनमें से 6 महिला स्वयं सहायता समूह हैं, जिनमें 60 सदस्य हैं। देवी रानी प्लास्टिक रीसाइक्लिंग, कंपोस्टिंग, कपड़े के थैले बनाने वाली इकाइयों में महिलाओं को शामिल करके, उनके आर्थिक सशक्तीकरण के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ काम कर रही हैं। वे अपने ज्ञान और अनुभव के माध्यम से शहर में कचरा चुनने वालों के लिए क्षमता निर्माण और उनके परिवारों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाओं की सुविधा प्रदान कर रही हैं।

₹ बजट 2023-24

प्रमुख घोषणाएं

"मैनहोल से मशीनहोल में परिवर्तन के जरिए सेप्टिक टैंक और सीवरों की मैकेनिकल सफाई के लिए सभी शहर और कस्बे आगे आएंगे।"

"सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टु वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे।"

"गीले और सूखे कचरे की वैज्ञानिक तौर पर प्रोसेसिंग करने की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।"

-श्रीमती निर्मला सीतारमण,
माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री

शहरी नियोजन, विकास और स्वच्छता पर पोस्ट बजट वेबिनार (1 मार्च, 2023)

अमृत काल बजट में अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर विशेष फोकस था। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बजट के बाद के वेबिनार में अपने विचार साझा किए।

हमारे नए शहरों को कचरा मुक्त, जल सुरक्षित और जलवायु के अनुकूल होना चाहिए। हमें टीयर 2 और 3 शहरों में और निवेश करना होगा।

नए शहरों का विकास 21वीं सदी में भारत की एक नई पहचान बनाएगा। शहरी विकास के लिए हमारे विजन के दो पहलु हैं: नए शहरों का विकास करना और पुराने शहरों में बेहतर सुविधाएं बढ़ाना।

शहरों के विकास के लिए फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, विशेष रूप से सर्कुलर इकोनॉमी में टैपिंग को तेज गति से अपनाया जाना चाहिए। मैं स्टार्टअप्स के जरिए नए रास्ते बनाने और मौजूदा अवसरों का उपयोग करने का आग्रह करता हूं।

हमारे शहरों के विकास के साथ-साथ मानव-केंद्रित विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

- नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

8वीं एनएआरसी बैठक
(नैशनल एडवाइजरी एंड रिव्यू कमिटी)

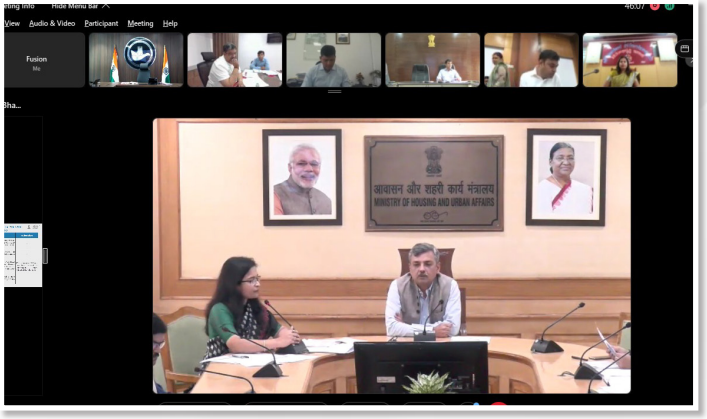

स्वच्छ भारत मिशन शहरी की 8वीं नैशनल एडवाइजरी एंड रिव्यू कमिटी की बैठक का आयोजन 6 मार्च 2023 को आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी की अध्यक्षता में 17 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कार्य योजना की समीक्षा करने के लिए किया गया था। इस दौरान एसबीएम-यू 2.0 के तहत 3,000 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है।

21 दिसंबर 2022 को आयोजित 7वीं एनएआरसी मीटिंग के मिनट्स के संबंध में कार्यवाही और एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) की पुष्टि।

राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त सीएस फंड रिलीज प्रस्तावों का अप्रूवल

एसबीएम-यू के तहत वित्तीय ब्योरा और फंड्स की पूरी स्थिति

एसबीएम-यू के बिना क्लेम किए गए फंड्स का एसबीएम-यू 2.0 के तहत उपयोग

चुने गए राज्यों द्वारा एसबीएम-शहरी के तहत रिलीज किए गए फंड्स का प्रस्तावित पुर्नआवंटन

क्षमता निर्माण के लिए प्रयास

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रूपा मिश्रा ने 16 मार्च 2023 को नगरपालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में जैव-मीथेनेशन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय सक्षम ढांचे पर कार्यशाला को संबोधित करते हुए एक सक्षम ईकोसिस्टम बनाने के महत्व पर जोर दिया।

हुडको के एचएसएम इंस्टीट्यूट में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के डायरेक्टर श्री बिनय कुमार झा ने 6 सप्ताह के एमईए-आईटेक कार्यक्रम में 7 फरवरी 2023 को 20 देशों से आए 24 प्रतिभागियों को संबोधित किया। यहां उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में भी जानकारी दी।

साझेदारी

केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने 2 मार्च 2023 को बिल गेट्स से मुलाकात के दौरान उनकी वर्तमान में चल रही साझेदारी और आगे के विभिन्न सहयोग के क्षेत्रों, विशेष रूप से शहरी स्वच्छता और भारत के ऊर्जा परिवर्तन को प्रोत्साहित करने के लिए इथेनॉल मिश्रण के प्रयास तेज करने पर चर्चा की।

दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के प्रयास

फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आधारित गोबरधन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसका उद्देश्य 19,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी गैस उत्पन्न करना है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत गोबरधन और SATAT योजनाओं से जुड़े जैव-मिथेनेशन प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में बायो-सीएनजी का उत्पादन करेंगे। इस विजन को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 1 फरवरी 2023 को ईआईएल के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए, ताकि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 'अपशिष्ट से ऊर्जा' और जैव-मिथेनेशन बनाने की परियोजनाओं को विकसित किया जा सके। इस एमओयू पर मंत्रालय के सचिव श्री मनोज जोशी, एसबीएम-यू राष्ट्रीय मिशन निदेशक एवं संयुक्त सचिव श्रीमती रूपा मिश्रा और ईआईएल की सीएंडएमडी वर्तिका शुक्ला की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

पूरी तरह कचरा मुक्त शहर बनाने के विजन के साथ स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्थायी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बड़े पैमाने पर ठोस अपशिष्ट के प्रोसेसिंग की सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। ईआईएल अपशिष्ट प्रबंधन में सर्कुलैरिटी लाकर बड़ी मात्रा में एकीकृत किए जाने वाले कचरे के लिए ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने में मिलियन प्लस शहरों की और सहायता करेगा। पहले चरण में बड़े पैमाने पर प्रोसेसिंग प्लांट विकसित करने के लिए 25 मिलियन से अधिक शहरों का चयन किया जाएगा। इन परियोजनाओं की सफलता महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ऐसी परियोजनाओं के लिए इसे बेंच-मार्किंग के रूप में क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रकार प्रारंभिक तकनीकी मूल्यांकन और लेनदेन सलाहकार सेवाओं में सहायता प्रदान करने के लिए ईआईएल से सहयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। ईआईएल निर्माण चरण के दौरान इन पीपीपी परियोजनाओं की निगरानी प्रक्रियाओं को पूरा करने में यूएलबी को भी मदद करेगा और वैधानिक अप्रूवल प्राप्त करने में सहायता करेगा। इस पहल के परिणामस्वरूप बायो-मिथेनेशन के लिए क्रमश: 15,000 टीपीडी और अपशिष्ट से ऊर्जा के लिए 10,000 टीपीडी की अतिरिक्त प्रोसेसिंग क्षमता होगी।

यू-20 इवेंट्स

नैशनल यूथ कॉन्क्लेव 2023

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 15 मार्च 2023 को दो दिवसीय नैशनल यूथ कॉन्क्लेव में माननीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, माननीय राज्य मंत्री श्री कौशल किशोर, माननीय जी-20 शेरपा-इंडिया श्री अमिताभ कांत और अन्य प्रतिष्ठित हस्तियां मौजूद रहीं। कॉन्क्लेव में देश भर के युवाओं ने भाग लिया, जिसमें विभिन्न रोमांचक प्रतियोगिताओं, समृद्ध चर्चाओं और सूचनात्मक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। इसमें शहरी विकास के प्रमुख पहलुओं और शहरी परिदृश्य में निर्णय लेने की प्रक्रिया में युवाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला गया।

यू-20 स्थापना बैठक

9 फरवरी 2023 को गुजरात के अहमदाबाद में वैश्विक चुनौती से निपटने और शहरी विकास में सकारात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से यू-20 इंसेप्शन मीटिंग हुई।

स्वच्छ होली-वोकल फॉर लोकल

> हमें 'वोकल फॉर लोकल' के संकल्प के साथ होली का त्योहार मनाना चाहिए
> – पीएम नरेंद्र मोदी

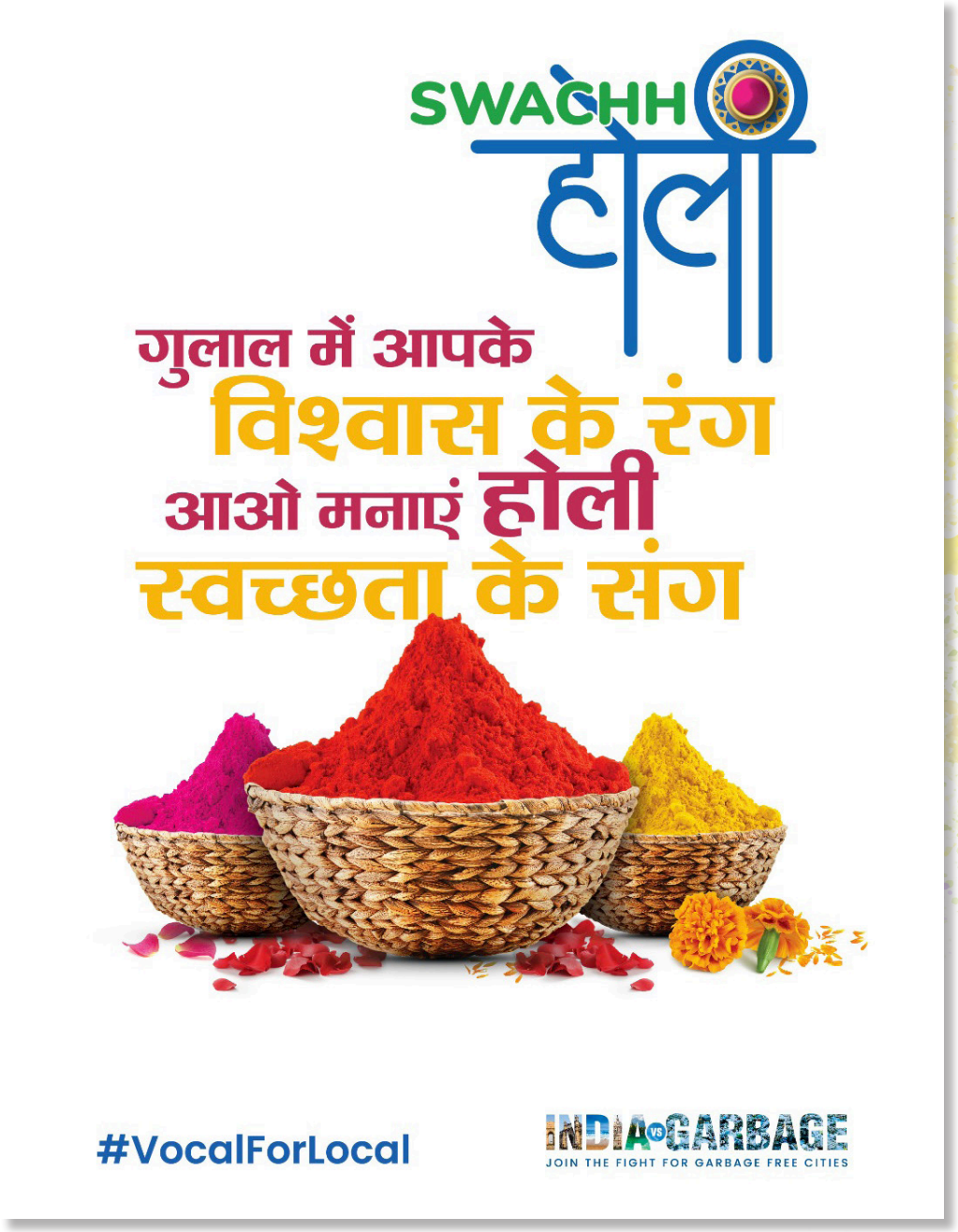

स्वच्छ होली-वोकल फॉर लोकल

पुराने समय की प्रथाओं को बढ़ावा देते हुए देशभर के विभिन्न राज्यों में मालाबार पालक, हल्दी, मेहंदी, चुकंदर आदि से रंग बनाए जा रहे हैं।

सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल की गृहणियों ने गेंदा, पालक, गुलाब, गाजर, चुकंदर और टैल्कम पाउडर जैसी प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग करके हर्बल रंग बनाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने 10 किस्मों में पर्यावरण के अनुकूल लगभग 80 किलोग्राम रंगों का उत्पादन किया।

जहां राष्ट्रीय राजधानी रंगों के त्योहार होली के जश्न में डूबी रही। वहीं महिलाओं की एक समर्पित टीम फूलों की पंखुड़ियों से रंग-बिरंगे गुलाल बनाने में जुटी हुई थी, ताकि त्योहार सुरक्षित, जैविक और स्वच्छ बन सके।

विटा नगर परिषद की ओर से स्कूली बच्चों ने ईको फ्रेंडली और स्वच्छ होली मनाई। छात्रों ने जल संरक्षण और स्वच्छ-हरित वीटा की शपथ ली।

स्वच्छ होली-वोकल फॉर लोकल

'वोकल फॉर लोकल' के विजन के तहत असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा को माननीय मंत्री श्री अशोक सिंघल द्वारा बांस की पिचकारी और जैविक रंग भेंट किए गए।

चंडीगढ़ में भी स्वच्छ होली मनाई गई। एसबीएम-यू 2.0 और एनयूएलएम के अंतर्गत एक एसएचजी कार्यकर्ता कुमकुम ने मंदिरों से निकलने वाले फूलों के कचरे से हर्बल और जैविक रंग बनाए। इससे जल निकायों में प्रदूषण को रोका जा सकेगा।

तेलंगाना के नालगोंडा में सब्जियों, फलों, पत्तियों और फूलों से बने प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल कर 'स्वच्छ होली' को अपनाया गया।

ओडिशा के गजपति जिले में स्वयं सहायता समूहों ने चुकंदर, मकई के आटे और चावल के आटे जैसी खाने की चीजों से बने रंगों के जरिए होली मनाई।

स्वच्छता के लिए मैदान में उतरे शहर

मध्य प्रदेश में रीवा की 150 साल पुरानी पुष्करणी बावड़ी में सफाई और सौंदर्यीकरण अभियान चलाया गया

गणतंत्र दिवस पर चंडीगढ़ की स्वच्छ झांकी में चार अलग-अलग रंगों के डिब्बे दिखाती बोगियों वाली ट्रेन का प्रदर्शन किया गया, जिसे स्वच्छता एक्सप्रेस का नाम दिया गया

उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कुछ जगहों पर ऐसी आकर्षक प्रतिमाएं स्थापित की गईं, जिनका निर्माण वेस्ट मटीरियल के इस्तेमाल से किया गया है

स्वच्छता के लिए मैदान में उतरे शहर

प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल रोक कर उसकी जगह लेने वाले कपड़े के थैले मुहैया कराने के लिए इंदौर में 56 अलग-अलग जगहों पर 'थैला एटीएम' नाम की क्लोथ बैग वेंडिंग मशीन लगाई गई

गाजियाबाद नगर निगम में गीले कचरे से कंपोस्टिंग के जरिए खाद बनाई जा रही है

पर्वतारोही अंजना यादव ने लेह में लद्दाख के चांगला पास पीक तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया

उत्तराखंड में लोहावती नदी के तटीय इलाकों में 36वीं वाहिनी, आईटीबीपी के हिमवीरों ने सफाई अभियान चलाया

फील्ड विजिट

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव एवं स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय मिशन निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा ने 12 जनवरी 2023 को दिल्ली के ओखला डंपसाइट का दौरा किया। यहां अब तक 23 लाख टन कचरे को निस्तारित किया जा चुका है, जबकि कुल 60 लाख टन कचरे को निस्तारित करने का लक्ष्य है।

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय मिशन निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा ने तेहखंड में 2,000 टन प्रतिदिन क्षमता वाले वेस्ट टु एनर्जी प्लांट और ओखला में 1,950 टन प्रतिदिन निस्तारण क्षमता वाले वेस्ट टु एनर्जी प्लांट का निरीक्षण किया

फील्ड विजिट

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त सचिव और स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय मिशन निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा ने गोवा के पणजी में 12 फरवरी 2023 को स्वच्छता केंद्र का दौरा किया। यह प्लांट 3R (रिड्यूज, रीसाइकल, रियूज) की प्रक्रिया को सुगम बना रहा है।

कॉलोनी स्तर पर अलग-अलग अपशिष्ट प्रबंधन, सामग्री की छंटाई संबंधी सुविधाओं में युवाओं और महिलाओं की भागीदारी, वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करने के लिए एसपीवी-गोवा अपशिष्ट प्रबंधन कंपनी की संस्थागत संरचना; गोवा को स्वच्छ रखने के लिए राज्य ने विभिन्न मैकेनिज्म लगाए हैं

14 फरवरी 2023 को एसोचैम के साथ साझेदारी में गोवा राज्य शहरी विकास एजेंसी और एएससीआई द्वारा इंक@वॉश का आयोजन किया गया। 800 से अधिक स्टार्टअप्स में से 50 को स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन और जल सुरक्षा में गोवा आधारित समाधानों के चलते चुना गया।

फील्ड विजिट

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशक श्री बिनय कुमार झा के नेतृत्व में स्वच्छ भारत मिशन-शहरी टीम ने विशाखापत्तनम में एकीकृत वेस्ट टु वेल्थ परिसर का दौरा किया। कॉम्प्लेक्स में 1100-1200 टीपीडी कचरे के फीड के साथ 15 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट टु एनर्जी प्लांट स्थित है।

MoHUA की टीम ने डॉ. वीके चौरसिया, संयुक्त सलाहकार, पीएचईई, सीपीएचईईओ के नेतृत्व में मैसूर जिले के नरसीपुर स्थित तिरुमलकुडु में एसटीपी का दौरा किया। यहां MBR तकनीक का उपयोग करके 5.5 MLD की क्षमता के साथ 2019 में प्लांट की स्थापना की गई थी। 35,000 से अधिक आबादी की जरूरतों को पूरा करने वाला यह प्लांट लगभग 3.6 एमएलडी सीवेज का शोधन करता है।

विश्व जल दिवस - ग्राउंड रिपोर्ट्स

225 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का सबसे तेज निर्माण और संचालन

इस परियोजना का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना था कि बुद्ध दरिया में केवल घरेलू रूप से उपयोग किए गए पानी या ताजे/बरसाती पानी का प्रवाह हो, जिससे भूजल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। पंजाब वॉटर सप्लाई एंड सीवेज बोर्ड की देखरेख में खिलारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 255 एमएलडी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की शुरुआत की गई। 2 दिसंबर 2022 को टीम ने इस परियोजना को पूरा किया, जो 17 मार्च 2021 को शुरू हुई थी। यानी कोविड-19 महामारी की चुनौतियों के बावजूद यह परियोजना 625 दिनों में पूरी हो गई। बिजली की गति से पूरी हुई इस परियोजना को इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया था।

संचालन और मरम्मत की लागत निकालने के लिए एक यूनीक रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल के साथ एसटीपी

तिरुपति, एक ऐसा शहर जिसने पिछले कुछ वर्षों में कई ख्यातियां अर्जित की हैं, जैसे कि उन 3 शहरों में से एक होना, जिन्हें वॉटर+ घोषित किया गया है। साथ ही एसटीपी के लिए एक आत्मनिर्भर मॉडल विकसित करने की बात करें, तो उसमें भी सबसे आगे है। थुकिवाकम में स्थित एसटीपी 19 करोड़ की लागत से बनाया गया था और इसकी क्षमता 50 एमएलडी है, जिससे 1,04,057 परिवार लाभान्वित होते हैं। सीवरेज कन्वेयंस सिस्टम के माध्यम से प्राप्त तरल अपशिष्ट (31.5 एमएलडी सीवरेज) और फीकल कीचड़ (1.5 एमएलडी) को एसटीपी-एफएसटीपी को-ट्रीटमेंट फेसिलिटी में ट्रीट किया जा रहा है। एसटीपी से ट्रीट किए हुए पानी की 24 एमएलडी मात्रा का पुन: उपयोग किया जाता है। श्रीकलाहस्ती पाइप्स लिमिटेड और प्लांट ट्रीट किए हुए 5 एमएलडी पानी को बेचकर से 6 लाख प्रति माह रुपये का नेट रेवेन्यू जनरेट करने में सक्षम है। इसके अतिरिक्त 18 एमएलडी शोधित पानी किसानों को कृषि के लिए नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाता है और इसके एक अन्य हिस्से का यूएलबी द्वारा शहर में सड़क/गलियों की सफाई, सड़कों के बीचों-बीच और पार्कों-बगीचों में पानी देने के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। एसटीपी के स्थायी ओपरेशन एंड मेंटिनेंस को सुनिश्चित करने के लिए यूएलबी द्वारा अपनाए गए अनूठे उपाय अनुकरणीय हैं।

विश्व जल दिवस - ग्राउंड रिपोर्ट्स

जीपीआरए कॉम्प्लेक्स - किदवई नगर (ईस्ट) - जीरो डिस्चार्ज कॉलोनी

ईस्ट किदवई नगर केंद्र सरकार की जीपीआरए कॉलोनी है जिसका निर्माण पुरानी सरकारी हाउसिंग कॉलोनी का पुनर्विकास करके किया गया है। पुरानी कॉलोनी में 2,444 घर (टाइप I, II और V) खराब अवस्था में थे और कुछ सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स थीं। पुनर्विकास के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के साथ 4,608 घर (टाइप ii से vii) समेत सरकार और पीएसयू के लिए 1.05 लाख वर्गमीटर ऑफिस बिल्डिंग्स का निर्माण किया गया है। किदवई नगर (ईस्ट) कैंपस जीरो वेस्ट डिस्चार्ज कॉलोनी है। यह कैंपस 23.43% ग्राउंड कवरेज और 15,000 से अधिक पेड़ों समेत 47% हरित क्षेत्र के साथ आर्थिक और पर्यावरण के नजरिए से आत्मनिर्भर है। यह कैंपस 'वॉक टू वर्क' की कॉन्सेप्ट पर आधारित है, जिसे कार्यालयों के रूप में 10% आवासीय इकाइयों को पट्टे पर देकर हासिल किया गया है। इससे सड़कों पर ट्रैफिक में भी कमी आई है।

किदवई नगर ईस्ट को जीरो वेस्ट डिस्चार्ज कॉलोनी बनाने की प्रक्रिया 3.65 एमएलडी क्षमता के एसटीपी प्लांट्स, वर्षा जल संचयन प्रणालियों और 3.5 टीपीडी के एक इन-हाउस ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट में इस्तेमाल किए गए पानी के ट्रीटमेंट द्वारा पूरी की गई है। फ्लैटों से निकलने वाले उपयोग किए गए पानी को एसटीपी प्लांट्स में ट्रीट किया जा रहा है, जिसके चलते नगर निगम की सीवर लाइन में ज्यादा पानी नहीं पहुंचता। एसटीपी से ट्रीट किए गए पानी का उपयोग शौचालयों में फ्लशिंग (इस उद्देश्य से दोहरी पाइपलाइन बिछाई जाती है), बागवानी, एयर कंडीशनिंग, सड़क की सफाई आदि के लिए किया जा रहा है। रसोई और बागवानी से निकलने वाले वेस्ट को एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्लांट में ट्रीट किया जा रहा है, जिससे बायो गैस निकलती है और बिजली भी पैदा हो रही है। इसके अलावा वर्षा जल संचयन प्रणालियों के माध्यम से वर्षा जल इस्तेमाल भी हो रहा है, फिर वह फिल्टर होकर भूजल स्तर में भी सुधार कर रहा है। जीरो-डिस्चार्ज होने से जो लाभ होते हैं, उसकी वजह से जल आपूर्ति देने वाले निकायों पर जल का भार कम होता है और भूजल स्तर में भी सुधार होगा।

छोटे शहरों में यूज्ड वॉटर मैनेजमेंट पर स्वच्छ टॉक्स वेबिनार

22 मार्च 2023 को विश्व जल दिवस के अवसर पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा 'छोटे शहरों में उपयोग किए गए जल प्रबंधन' विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। स्वच्छ टॉक्स में प्रयुक्त जल प्रबंधन परियोजनाओं के डिजाइन और लागू करने में छोटे शहरों द्वारा सर्कुलर इकोनॉमी विजन को अपनाने, सर्वोत्तम प्रयासों को प्रदर्शित करने के बारे में चर्चा शामिल थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, एसबीएम 2.0 के तहत राज्यों के लिए 4,918.91 एमएलडी, आई एंड डी नेटवर्क और डीस्लजिंग वाहनों की क्षमता वाले एसटीपी की स्थापना के लिए 11,784.81 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को पहले ही मंजूरी दे दी गई है।

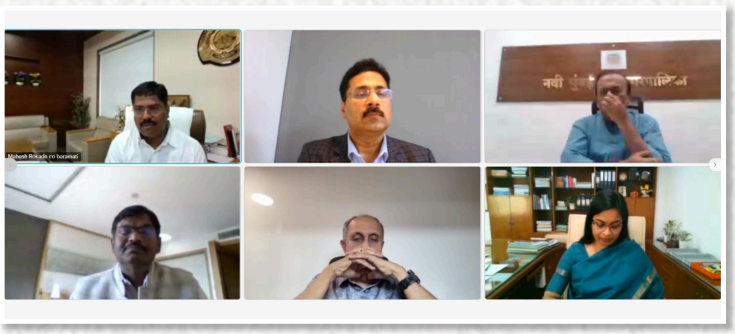

स्वच्छता खबरों में...

जागरण विशेष

अब रोबोट से हो सकेगी सीवरेज पाइपलाइन की सफाई

स्वच्छता में इंदौर का एक और नवाचार, गैस सेंसर और कैमरों से तुरंत पता लग सकेगा कहां है लीकेज

उदय प्रताप सिंह ● इंदौर

पाइपलाइन की सफाई के लिए बनाए रोबोट का परीक्षण करते शुभम।

स्वच्छता में छह बार देश का नंबर वन शहर इंदौर अपने नवाचारों के लिए भी पहचाना जाता है। नगर निगम द्वारा अभी शहर में सीवरेज की सफाई के लिए रोबोटिक मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन इन मशीनों से फिलहाल सिर्फ चैंबरों की सफाई ही हो पाती है। यदि सीवर पाइपलाइन में खराबी या लीकेज है तो उसे ठीक करने के लिए खोदाई करनी होती है। शहर के कुछ युवाओं ने अपने स्टार्टअप के माध्यम से इस समस्या का हल भी खोज लिया है। यहां ऐसे रोबोट तैयार किए जा रहे है, जिनसे ड्रेनेज चैंबर के अलावा सीवरेज पाइपलाइन की सफाई भी की जा सकती है। इसकी रोबोटिक भुजा पाइप लाइन में जमी गंदगी व ब्लाकेज को भी हटा सकेगी। इसमें गैस सेंसर, कैमरे भी लगे हुए हैं। इसकी मदद से रोबोट पाइपलाइन के लीकेज की जानकारी देने के साथ यह भी बता देगा कि कहां गैस बन रही है। इससे सुधार कार्य के लिए होने वाली खोदाई से तो मुक्ति मिलेगी ही खोदाई से अस्तव्यस्त होने वाले यातायात से भी राहत मिलेगी। एक माह में यह रोबोट निगम को सौंप दिया जाएगा। उसके बाद निगम क्षेत्र में इसके माध्यम से सफाई होने लगेगी।

सांप की तरह पाइप लाइन में पहुंचेगा रोबोट: शोध करने वाले आर्क रोबोटिक्स के सदस्य शुभम विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा और जितेंद्र दुबे मैकेनिकल और कंप्यूटर इंजीनियर हैं। इन्होंने इस रोबोट को एक साल शोध के बाद बाद तैयार किया है। इसमें रोबोटिक्स भुजा का उपयोग किया गया है, जो सांप की तरह लचीली है और 360 डिग्री पर घूम कर पाइप लाइन के भीतर सफाई करने में सक्षम है। इसके मुहाने पर लगा ग्रैबर भीतर जमी गाद आदि को खींचकर बाहर निकालता है। प्रोटोटाइप माडल में इस आर्म की लंबाई 12 फीट रखी गई है। इसे बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन फिलहाल इसका परीक्षण किया जाना है कि यह कितनी लंबाई तक कार्य करने में सक्षम है।

बारिश में ड्रेनेज चैंबर ओवर फ्लो की देगा चेतावनी: राहुल विश्वकर्मा के मुताबिक, रोबोट ड्रेनेज चैंबर की सफाई के दौरान यह आकलन भी करेगा कि पाइपलाइन में कितनी गाद आ रही है और पानी की स्थिति क्या है। पाइपलाइन में सीवरेज का बहाव भी रोबोट के साफ्टवेयर में दर्ज हो जाएगा। पानी के बहाव की जानकारी मिलने से बारिश के पहले यह आकलन करने में भी मदद मिलेगी कि किन इलाकों के ड्रेनेज चैंबर ओवरफ्लो हो सकता है। ऐसे में निगम पहले ही वहां सफाई और सुधार कार्य करवाकर क्षेत्र में जलजमाव की स्थिति रोक सकेगा। इस रोबोट को टच स्क्रीन वाले कंट्रोल पैनल से जोड़ा है। इससे पाइप लाइन के अंदर की स्थिति स्क्रीन पर दिखाई देगी।

रोबोट का ग्राफिक्स प्रस्तुतीकरण चित्र, इस तरह करेगा चैंबर और पाइप लाइन की सफाई

युवाओं द्वारा बनाए गए इस रोबोट से सीवरेज लाइन के चैंबर के अलावा पाइपलाइन के इनलेट व आउटलेट तक पहुंचकर सफाई की जा सकेगी। युवाओं द्वारा तैयार रोबोट का प्रोटोटाइप फरवरी माह की शुरुआत तक निगम को डेमो के लिए मिल जाएगा। **सिद्धार्थ जैन**, अपर आयुक्त, इंदौर नगर निगम

मल्टीपल सेंसर के साथ छोटा रोबोट बता देगा पाइपलाइन की लीकेज व दरारें

राहुल के मुताबिक रोबोटिक्स आर्म्स में से एक छोटा रोबोट निकलेगा जो सीवरेज लाइन का निरीक्षण कर यह बता देगा कि पाइपलाइन कहां से फूटी है और कहां पेड़ों की जड़े फंसने की वजह से बहाव में परेशानी है। चैंबर का ढक्कन खोलने के दौरान निकलने वाली गैस से बाहर खड़े कर्मचारियों को परेशानी होती है। इस रोबोट में लगे गैस सेंसर ये भी बता देंगे कि दो चैंबरों के बीच कितनी गाद जमा है और उनमें कितनी मीथेन या अन्य प्रकार की गैस हो सकती है।

विस्तार से पढ़ने के लिए स्कैन करें।

पटना नगर निगम द्वारा शुरू किया जा रहा सैनिटरी मार्ट

नगर निगम द्वारा चल रहे वाहन के स्पेयर पाट्र्स एवं सेनिटेशन सामग्री हर वक्त मौजूद रहेगी

नगर निगम द्वारा गुणवत्ता की होती रहेगी जांच, रजिस्टर्ड एजेंसियों द्वारा ही लिया जाएगा पाट्र्स एवं मटेरियल

सुनील कुमार की रिपोर्ट

पटना। नगर निगम द्वारा सैनिटेशन मार्ट की शुरूआत की जा रही है। पटना नगर निगम के इस सैनिटेशन मार्ट में वाहनों के स्पेयर पार्ट, टायर - ट्यूब विभिन्न सामग्रियां मौजूद रहेंगी जिससे गाड़ियों में किसी भी तरह की कमी होने पर तुरंत उसे रिपेयर किया जा सके।

जिससे आम जनों को मिलने वाली सफाई एवं अन्य तरह की सुविधाओं में वाहनों के कारण कोई समस्या ना आए। गौरतलब है कि नगर निगम के इस सैनिटेशन मार्ट में रजिस्टर्ड एजेंसियों द्वारा पाट्र्स उपलब्ध करवाए जाएंगे एवं उनकी गुणवत्ता की जांच नगर निगम के स्तर पर हो सकेगी जिससे वाहनों में जल्दी से खराबी ना आए एवं कम गुणवत्ता वाले पाट्र्स आदि की समस्या की शिकायत दूर हो सके। इसके साथ ही सफाई में इस्तेमाल होने वाले चूना ब्लीचिंग पाउडर झाड़ू खुदा बेरछा आदि सभी सामग्रियों इस मार्ट में मौजूद रहेंगे।

अगले महीने से मिलेगी सुविधा

बता दें कि पटना नगर निगम द्वारा यह सेनेटरी मार्ट बनकर तैयार हो चुका है। नगर आयुक्त द्वारा निर्देश दिया गया है की अगले माह से यह सैनिटरी मार्ट शुरू कर दिया जाएगा। पहले चरण में इसे नूतन राजधानी अंचल में शुरू किया जा रहा है। जिसके बाद अन्य अंचलों में भी इसकी सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

सैनेटरी मार्ट की विशेषताएं

1. इस तरह की सुविधा पहली बार पटना नगर निगम में उपलब्ध कराई जा रही है।
2. आवश्यकता की पूर्ति के अनुरूप पहले से ही पाट्र्स मौजूद होंगे जिससे आसानी से वाहनों को रिपेयर किया जा सके।
3. पटना नगर निगम द्वारा रजिस्टर्ड एजेंसी के ही पाट्र्स ही उपलब्ध होंगे।
4. नगर निगम द्वारा गुणवत्ता के सभी मानकों की मॉनिटरिंग की जाएगी।
5. आवश्यक पाट्र्स एवं सैनिटेशन सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगी जिससे किसी भी तरह की स्थिति होने पर नगर निगम उसका निराकरण कर सकता है।
6. वाहनों की खराबी के कारण सेवा में विलंब नहीं होगा

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट विकसित करने के लिए 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के साथ किए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

दबंग रिपोर्टर » मुंबई

माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने साल 2023-2024 का बजट पेश किया, जिसमें अमृतकाल के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करने वाली सात प्राथमिकताओं या सप्तऋषि को सूचीबद्ध किया है। इन प्राथमिकताओं में हरित विकास खंड के तहत सूचीबद्ध सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए गोबर-धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स की स्थापना का प्रस्ताव रखा। कुल 10,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ इनमें 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट, 75 शहरी क्षेत्रों में, 300 समुदाय या क्लस्टर-बेस्ड प्लांटशामिल होंगे।

इस विजन को ध्यान में रखते हुए आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (टङ्खल्ठवअ) की संयुक्त सचिव एवं स्वच्छ भारत मिशन की राष्ट्रीय निदेशक श्रीमती रूपा मिश्रा और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) के कार्यकारी निदेशक श्री आरके राठी ने मंत्रालय सचिव श्री मनोज जोशी और ईआईएल की सीएंडएमडी वर्तिका शुक्ला की उपस्थिति में दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मिथेनेशन प्रोजेक्ट्स विकसित करने के लिए एक (एमओयू) समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

कचरा मुक्त शहर बनाने के विजन से स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के अंतर्गत स्थायी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर जोर दिया गया है। इस उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रालय ने दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बड़े पैमाने पर सॉलिड वेस्ट प्रोसेसिंग की सुविधाएं स्थापित करने का निर्णय लिया है। भारत में लखनऊ, कानपुर, बरेली, नासिक, ठाणे, नागपुर, ग्वालियर, चेन्नई, मदुरै, कोयंबटूर जैसे दस लाख से ज्यादा आबादी वाले 59 शहर हैं। इन दस लाख से ज्यादा आबादी वाली श्रेणी के शहरों में म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट को बायो-मिथेनेशन प्लांट्स के जैविक/गीले अंश के मैनेजमेंट के लिए प्रस्तावित किया गया है।

फरवरी 2022 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में एशिया के सबसे बड़े म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट बेस्ड गोबर-धन प्लांट का उद्घाटन किया, जिसका लक्ष्य 19,000 किलोग्राम बायो-सीएनजी गैस उत्पन्न करना है। स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत, गोबर-धन और सतत योजनाओं से जुड़े ये बायो-मिथेनेशन प्लांट अक्षय ऊर्जा के रूप में बायो-सीएनजी का उत्पादन करेंगे।

वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट से आने वाले सूखे कचरे के अंश का उपयोग करते हैं और एसडब्ल्यूएम नियम 2016 का अनुपालन करते हुए निस्पादन में कम से कम जगह का उपयोग करके कचरे की मात्रा में अधिकतम कमी के साथ अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण के वैधानिक मानदंडों को पूरा करते हैं। वेस्ट टू एनर्जी और बायो-मीथेनेशन प्रोजेक्ट्स म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट के सूखे और गीले कचरे के अंश घटक से हरित ऊर्जा का उत्पादन करके वेस्ट मैनेजमेंट में सकुलैंरिटी की अवधारणा को एकीकृत करेंगे। बिजली और बायो-सीएनजी जैसे बाइ-प्रोडक्ट भी वेस्ट मैनेजमेंट के कामों में स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेंगे।

ईआईएल, वेस्ट मैनेजमेंट में सकुलैंरिटी को एकीकृत करने वाले कचरे की बड़ी मात्रा के लिए ऐसी परियोजनाओं को विकसित करने में इन शहरों की सहायता करेगा। पहले चरण में, 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 25 शहरों को बड़े पैमाने पर कचरे से बिजली और बायो-मीथेनेशन विकसित करने के लिए चुना जाएगा। इन परियोजनाओं की सफलता महत्वपूर्ण होगी क्योंकि ऐसी परियोजनाओं के लिए इसे मील के पत्थर के रूप में अवधारित और क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रकार, इस साझेदारी में ईआईएल द्वारा प्राप्त प्रारंभिक तकनीकी मूल्यांकन और ट्रांजेक्शन एडवाइजरी सेवाओं में किए जा रहे सहयोग का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। निर्माण के दौरान ईआईएल इन पीपीपी प्रोजेक्ट्स की निगरानी करने में शहरी स्थानीय निकायों की मदद करेगा और वैधानिक अनुमोदन भी प्राप्त करने में मदद करेगा।

दस लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों के लिए ये प्रोजेक्ट्स अतिरिक्त 15,000 टीपीडी जैव-मिथेनेशन क्षमता और 10,000 टीपीडी वेस्ट टू एनर्जी क्षमता स्थापित करने का लक्ष्य रखते हैं। शहरों को 'कचरा मुक्त' बनाने के विजन के तहत एसबीएम-यू 2.0 का ध्यान लेगेसी डंपसाइट्स, निर्माण और डेमोलेशन वेस्ट और प्लास्टिक वेस्ट प्रबंधन के बायो-उपचार के साथ-साथ 100% वेस्ट प्रोसेसिंग के लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित है।

Civic body to build 20,000 toilets in 2023-24

SHEFALI PARAB-PANDIT
MUMBAI

The BMC has planned to construct 20,000 new toilets in 2023-24 under the slum sanitation programme. Additionally, around 3,000 toilets constructed in the slums by the Maharashtra Housing and Area Development Authority (MHADA) will be operated and maintained by the BMC.

According to the Swachh Bharat Mission norms, the slum pockets should have one toilet for 35 males and 25 females. However, the city has one community toilet seat per 42 males and 34 females. Also, there is a lack of adequate public toilets for the transit population on the eastern and western highways. So the BMC has planned to build more toilets to match the user and toilets ratio.

Accordingly, around 20,000 toilet seats were reconstructed in Lot-11 under the slum sanitation programme. The civic body has announced the construction of 20,000 new toilets under Lot-12 in its budget for 2023-24. The BMC has also undertaken works to construct modern toilet facilities under the 'pay and use' model in wards located along the highway.

The BMC had floated a proposal to take over all public and community toilets from MHADA under the Swacch Bharat Mission in 2018. A survey in this regard was carried out by the contractor appointed by the BMC. "The report said that most of the toilets are in dilapidated condition. So now we will overtake 3,000 toilets constructed by MHADA and will operate and maintain them," said a civic official.

Public toilets to be cleaned five times a day

Structural audit of public toilets more than 30 years old conducted in 2018

BMC plans to increase public toilets, especially in slums and high footfall areas

महिलाओं के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ

दबंग रिपोर्टर » मुंबई

महिलाएं बदलाव लाने में योगदान दे सकती हैं। वे न केवल अपने घरों में बल्कि पूरे समाज में अनादि काल से स्वच्छता की ध्वजवाहक रही हैं। 8 मार्च को महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने महिलाओं के नेतृत्व वाले तीन सप्ताह तक चलने वाले स्वच्छता अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किया। इस उत्सव में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी से आगे बढ़कर महिलाओं के नेतृत्व वाली स्वच्छता को पहचाना और मनाया जा रहा है। कचरा मुक्त शहरों (जीएफसी) के मिशन को सफल बनाने में अपना नेतृत्व प्रदान करने वाली सभी क्षेत्रों की महिलाओं को समर्पित इस उत्सव को मनाने के लिए शहरों में कार्यक्रमों और गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी।

साल 2014 में जब स्वच्छ भारत मिशन की शुरूआती हुई, तब सफाई अभियानों में बड़े स्तर पर महिलाओं की भागीदारी देखी गई थी, जिनमें शौचालयों के इस्तेमाल के लिए जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छता की ओर अपनी तरह से योगदान देना शामिल रहा। वे पिछले आठ वर्षों में स्वच्छता स्पष्ट रूप से जन आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ के रूप में विकसित हो रही हैं, जैसे अन्य महत्वपूर्ण हितधारक, युवा और स्टार्टअप। मटीरियल रिकवरी फेसिलिटी सिस्टम के संचालन से लेकर वेस्ट टु वेल्थ स्टार्टअप शुरू करने तक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रबंधन से लेकर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने तक महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।

स्वच्छोत्सव के लॉन्च के दौरान ही विमन आइकॉन्स लीडिंग सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज-2023 की घोषणा भी की गई। विन्स चैलेंज-2023 शहरों में स्वच्छता हासिल करने की दिशा में काम करने वाली महिला उद्यमियों या महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को मान्यता देगा। विन्स अवॉर्ड्स-2023 के लिए नामांकन शुरू हो गए।

10 मार्च से स्वच्छता यात्रा की शुरूआत होगी, जो 30 मार्च को पूरी होगी, जिसे यूनाइटेड नेशन्स जनरल असेंबली द्वारा इंटरनैशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट के रूप में घोषित किया गया है। 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि इस यात्रा के हिस्से के रूप में 24 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का भ्रमण करेंगे। यह एकजुट होकर सीखने की एक तरह की अंतर-राज्यीय पहल है, जो एरिया लेवल फेडरेशन या स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को चयनित शहरों की 'स्वच्छता दूत' के रूप में यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

मैं भारत की पिछले 75 वर्षों की यात्रा में योगदान की तुलना में आगामी 25 वर्षों में 'नारी शक्ति', मेरी माताओं, बहनों और बेटियों के कई गुना योगदान देख सकता हूं ...जितना अधिक हम इस पहलू पर ध्यान देंगे, उतने ही अधिक अवसर और सुविधाएं हम अपनी बेटियों को दे सकते हैं, वे उससे कहीं ज्यादा हमें लौटाएंगी। वे देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाएंगी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा।

स्वच्छ ढाबा अभियान से बदलेगी यूपी की छवि

वरिष्ठ संवाददाता (vol)

लखनऊ। स्वच्छ भारत मिशन नगरीय 2.0 के तहत यूपी को स्वच्छ बनाने को लेकर स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) की ओर से पांच जनवरी से स्वच्छ ढाबा अभियान की शुरूआत की जा रही है। 12 जनवरी तक चलने वाले इस अभियान के तहत प्रदेश के 750 निकायों में संचालित ढाबों से निकलने वाले अपशिष्ट का वैज्ञानिक विधि से स्वतः निस्तारण के प्रति प्रेरित किया जाएगा। साथ ही, मानक पर खरा उतरने वाले ढाबों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। इन्हें एक स्टार, तीन स्टार और पांच स्टार रेटिंग जारी की जाएगी।

- 5 से 12 जनवरी के बीच चलेगा प्रदेशव्यापी अभियान
- रेटिंग के आधार पर प्रतिष्ठानों को किया जायेगा सम्मानित

राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन नेहा शर्मा ने बताया कि शासन के निर्देश पर प्रदेश के सभी 750 निकायों में स्वच्छ भारत मिशन नगरीय के अन्तर्गत पांच जनवरी से 12 जनवरी तक स्वच्छ ढाबा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत मुख्य मार्गों पर संचालित ढाबा/रेस्टोरेन्ट प्रतिष्ठानों से प्रतिदिन भारी मात्रा में निकलने वाले अपशिष्ट को वैज्ञानिक विधि से स्वतः निस्तारित करने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि निकायों में संचालित ढाबों अथवा रेस्टोरेंटों का निरीक्षण एक विशेष टीम द्वारा किया जाएगा। जिसके बाद मापदंडों पर खरा उतरने वाले प्रतिष्ठानों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्वच्छ ढाबा अभियान के जरिए एक ओर जहां ढाबों में स्वच्छता सुनिश्चित होगी वहीं इन ढाबों अथवा रेस्टोरेंटों पर भारी संख्या में पहुंचने वाले राहगीर भी स्वच्छता के प्रति

जागरूक होंगे। स्वच्छ ढाबा अभियान उत्तर प्रदेश के आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरुक करने में मील का पत्थर साबित होगा। यह अभियान तीन माह तक चलाया जाएगा। पांच से 12 जनवरी तक चिन्हित ढाबों पर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन होगा। 13 जनवरी से 20 मार्च 2023 चिन्हित ढाबों की मॉनिटरिंग, 20 मार्च से 31 मार्च तक रेटिंग के आधार पर ढाबों का पुरस्कार वितरण होगा।

ढाबे पर बेकार सामग्री से बने सामानों का लगाना होगा स्टाल : सिंगल यूज प्लास्टिक और प्लास्टिक कटलरी का प्रयोग ढाबे में नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक उपयोग के लिए 2 डिब्बे (हरे और नीले) ढाबे में लगे होने चाहिए। ढाबों को गीले और सूखे कचरे का निपटान, शौचालय साफ एवं उपलब्ध हों, ओडीएफ श्रेणी की सभी शर्तों को पूरा हों, गूगल मैप या टॉयलेट लोकेटर पर ढाबे के शौचालय की लोकेशन अपलोड हो, ढाबों के आसपास कूड़े का ढेर नहीं होना चाहिए तथा ढाबों पर चित्रों के माध्यम से स्वच्छता का संदेश होना चाहिए। तीन स्टार के लिए 1 स्टार की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। गीले अपशिष्ट (कम्पोस्टिंग या कॉम्पैक्ट बायोगैस) की उपलब्धता होनी चाहिए। ढाबे में साफ पार्किंग, सफाई होना चाहिए। पांच स्टार के लिए 1 और 3 स्टार की सभी शर्तों को पूरा करना होगा। गीला और सूखा दोनों प्रकार के कचरे का पुनः उपयोग स्वयं के स्तर पर करना होगा। ढाबा जीरो वेस्ट हो और 3 आर (रिड्यूस, रि-यूस ओर रिसाइकिल) को फॉलो करना होगा। ढाबे पर वेस्ट टू वंडर (आइटम) / सेल्फी पॉइंट (कचरे से बना) बना होना चाहिए। ढाबे पर बेकार सामग्री से बने सामान को बेचने के लिए छोटा स्टॉल लगाना होगा, जिससे ढाबे पर आने वाले लोग उसको देखे और प्रोत्साहित हों।

प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी में दिन-रात एक करने वाले परदे के पीछे के असल हीरो

कड़कड़ाती ठंड में फर्ज को अंजाम देने वाले योद्धाओं को सलाम

आदित्य सिंह सोलंकी, इंदौर

शहर की साख माने जाने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जो चकाचौंध शहर में दिख रही है, दरअसल उस चकाचौंध के पीछे नगर निगम प्रशासन और पुलिस के कई योद्धाओं का सामर्थ्य है। इन्होंने दिन-रात कड़कड़ाती ठंड की परवाह किए बिना अपने फर्ज को अंजाम दिया। इसी का नतीजा रहा कि आज 70 देशों से आए प्रवासी भारतीय और वीवीआईपी डेलिगेट्स उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे।

दरअसल मप्र सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन शुरू किया गया। इसकी कमान तत्कालीन कलेक्टर मनीष सिंह को सौंपी गई। मनीष सिंह द्वारा प्रशासन, नगर निगम और पुलिस की टीम के सामर्थ्य पर इस आयोजन को सफल बनाने का बीड़ा उठाया गया। इसके चलते दिन-रात मेहनत कर इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाने के

काम का ब्लू प्रिंट तैयार हुआ और आज वह ब्लूप्रिंट दुनिया के सामने खड़ा है। जिसकी यादें संजोकर 70 देशों तक यह मान जाएंगे। दरअसल मनीष सिंह को मैन टू मैन मार्किंग करने में महारत हासिल है। यह उनके जमीनी अनुभव का असर है जो आज दुनिया के सामने खड़ा है। दरअसल इस काम के पीछे हजारों अन्य योद्धा भी शामिल हैं जिन्होंने अपने फर्ज को अंजाम दिया।

यह है निगम की जांबाज टीम-इंदौर शहर की प्रतिभा को दिखाने का असल जज्बा निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल में था। जिन्होंने कम समय में चुनौती को स्वीकार करते हुए नगर निगम की टीम के साथ शहर की तस्वीर बदल दी। 70 देशों तक इंदौर की ख्याति अगर पहुंचेगी तो उसके पीछे एक अहम नेतृत्व निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल और उनकी टीम का जाना जाएगा। क्योंकि कम समय में शहर का रंग रोगन करना, उसकी सजावट और प्रवासी भारतीयों की हर सुविधा और देखरेख को लेकर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल और उनके समस्त मातहतों द्वारा दिन-रात एक कर शहर की सूरत बदल दी गई। निगम के सफाईकर्मियों से लेकर निगम के अपर आयुक्त दिन-रात ड्यूटी में लगे रहे। बिना ठंड परिवार की परवाह किए उन्होंने जो श्रमदान किया है उसकी आज चारों तरफ चर्चाएं हैं।

प्रशासन का ऐतिहासिक योगदान

इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी के अथक प्रयास और जमीनी पकड़ का नतीजा रहा कि प्रशासन की टीम पूरे आयोजन में लामबंद रही। प्रशासनिक टीम के करीब 500 से ज्यादा छोटे-बड़े कर्मचारी और अधिकारियों ने पूरे आयोजन पर पैनी नजर बनाई। साथ ही कलेक्टर के कुशल नेतृत्व ने प्रत्येक प्रवासी भारतीय की मैपिंग कर उसके साथ व्यक्तिगत रूप से अधिकारियों का जुड़ाव कराया ताकि मेहमानों से अधिकारियों का सीधा संपर्क बना रहे और उन्हें किसी तरह की तकलीफ महसूस न हो। उनकी यह योजना पूर्णतः सफल साबित हुई और इंदौर की सरजमी पर लैंड करने के साथ आयोजन में शामिल होने और इंदौर के व्यंजनों का स्वाद चखने के दौरान हर जगह प्रशासन की टीम साए की तरह प्रवासी भारतीयों के साथ जुड़ी रही। प्रशासन के कर्मचारी और अधिकारियों ने भी दिन-रात की परवाह किए बगैर कड़कड़ाती ठंड में अपने फर्ज को अंजाम दिया जिसकी ख्याति का आज 70 देशों के लोग गुणगान कर रहे हैं।

पुलिस की सख्त मोर्चाबंदी, तीन हजार के बल ने बनाया सुरक्षा का मजबूत किला

किसी भी आयोजन की सुरक्षा का जिम्मा, एक मजबूत किले की तरह होता है और इस किले का नाम कानून व्यवस्था है। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र के कुशल नेतृत्व का ही अंजाम है कि आज पुलिस ने सुरक्षा की एक ऐसी दीवार बनाई जिसे अपराधी और अन्य असामाजिक तत्वों द्वारा भेद पाना असंभव था। उसी का नतीजा रहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित अन्य देशों के राष्ट्रपति और वीवीआईपी डेलिकेड सुरक्षित और सद्भाव पूर्ण वातावरण में इंदौर के आयोजन में शामिल हुए। इंदौर पुलिस के 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन-रात कड़कड़ाती ठंड में अपने फर्ज को अंजाम देते रहे। इनकी जिंदादिली, देशभक्ति और तत्परता का ही फलसफा है कि आज 70 देशों में इंदौर पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था के चर्चे हो रहे हैं।

लोगों को राहत | डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट, झूरीवाला से कूड़े व आरडीएफ उठवाने का काम जारी, कुछ दिन में ग्राउंड होगा साफ

बदबू हुई कम : डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट से उठाया 18,000 टन कूड़ा

सिटी रिपोर्टर | पंचकूला

डंपिंग प्रोसेसिंग प्लांट, झूरीवाला से कूड़े व आरडीएफ उठवाने का काम लगातार जारी है। नगर निगम की अधिकृत कंपनी ने कर्मचारी एवं मशीनरी के सहयोग से इस काम में तेजी लाई है। रोजाना सैकड़ों टन कूड़े से आरडीएफ (जलने वाला ईंधन) बनाने के लिए सोनीपत और बवाना के बिजली प्लांटों में भेजा जा रहा है। अब इस एरिया में बदबू की समस्या काफी हद तक खत्म हो गई है।

कंपनी के प्रबंधक मयंक मल्होत्रा ने बताया कि करीब दो महीने से प्रतिदिन 400 से 500 टन आरडीएफ (जलने वाला ईंधन) सोनीपत और बवाना के बिजली प्लांटों में भेजा जा रहा है। अगले कुछ दिन में डंपिंग ग्राउंड को पूरी तरह साफ कर दिया जाएगा। नगर निगम में चीफ सेनेटरी इंस्पेक्टर अविनाश सिंगला ने बताया कि शहर में डोर टू डोर गारबेज कलेक्शन का ठेका लेने वाली एजेंसी की ओर से डंपिंग ग्राउंड से कचरा उठाने के काम में तेजी लाने का असर दिखने लगा है। कचरे के ढेर कम होने से एरिया में बदबू कम होने से लोगों ने भी राहत की सांस ली है। बीते एक महीने में झूरीवाला से 18,000 टन कचरा उठाया जा चुका है। झूरीवाला डंपिंग ग्राउंड से रोजाना ट्रालों में भरकर यह कचरा सोनीपत के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में भेजा जा रहा है। रोजाना 10 से 12 ट्रालों में भरकर कचरा सोनीपत के लिए भेजा जा रहा है। लगभग 400 टन से ज्यादा कचरा रोजाना हटाया जा रहा है। अब यहां केवल आठ हजार टन के आसपास शेष कचरा बचा है, जिसे अगले कुछ दिनों में हटाने का लक्ष्य तय किया गया है। मुरथल में ताजपुर रोड पर स्थापित वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में कूड़े से बिजली व खाद का निर्माण किया जा रहा है। पंचकूला जिले में प्लांट लगने तक फिलहाल लोगों को कचरे से निजात दिलाने के लिए झूरीवाला में एकत्र कचरा सोनीपत जा रहा है। इस प्लांट में शुरुआत में प्रतिदिन करीब 411 टन कूड़े से बिजली बनाई जाती थी जो अब 650 टन के करीब पहुंच चुका है। भविष्य में लगभग 743 टन कूड़े से बिजली उत्पादन होगा। यहां सोनीपत, गन्नौर, समालखा व पानीपत का कूड़ा पहले से लाया जाता है। प्लांट में प्रति घंटे की दर से नौ मेगावाट बिजली बनाई जा रही है।

भास्कर खास • कछार में छत्तीसगढ़ का पहला वेस्ट डिस्पोजल प्लांट जिसकी छत पर सोलर पैनल लगा, खपत लायक बिजली बनाने का दावा, रायपुर में काम चल र

वेस्ट डिस्पोजल प्लांट खुद की बिजली से चल रहा, हर माह 3 लाख की बिजली बन रही

6 हजार वर्गफुट के शेड पर लगाया गया है सोलर पैनल

कछार प्लांट आत्मनिर्भर

सोशल मीडिया ट्रेंड्स

facebook

twitter

Instagram

स्वच्छ भारत मिशन पर ज्यादा जानकारी के लिए

हमें फॉलो करें

Swachh Bharat Mission – Urban | @SwachhBharatGov | sbm_urban | Swachh Bharat Urban | swachh-bharat-urban